OPEN ACCESS

Int. J. Creative Res. Publ. *Peer-Reviewed Journal* *Volume 1 Issue 4 [Jul-Aug] 2026*

I J C R P
International Journal of Creative Research and Publications
Double Blind Peer Reviewed Journal

Research Article

जयपुर जिले में इंदिरा गांधी शहरी रोजगार योजना: एक भौगोलिक विश्लेषण

तब्बसुम आरा [1*], डॉ. राम भावत सिंह [2]

[1] शोधार्थी, ज्योति विद्यापीठ महिला विश्वविद्यालय, जयपुर, राजस्थान, भारत
[2] शोध पर्यवेक्षक, ज्योति विद्यापीठ महिला विश्वविद्यालय, जयपुर, राजस्थान, भारत

Corresponding Author: *तब्बसुम आरा

DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.22687761

सारांश

यह लेख राजस्थान सरकार की इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना (जिसे अब मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना के नाम से जाना जाता है) का जयपुर जिले में भौगोलिक विश्लेषण प्रस्तुत करता है। सितंबर 2022 में शुरू की गई यह योजना, शहरी गरीब परिवारों को प्रति वर्ष 100 दिन (बाद में 125 दिन) का गारंटीशुदा रोजगार प्रदान कर आजीविका सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) की तर्ज पर तैयार की गई है। जयपुर में, योजना का क्रियान्वयन जयपुर नगर निगम (हेरिटेज और ग्रेटर) के माध्यम से किया गया है, जिसमें पर्यावरण संरक्षण, विरासत संरक्षण और स्वच्छता जैसे श्रम-आधारित कार्यों पर विशेष जोर दिया गया है।

विश्लेषण से पता चलता है कि योजना ने शहरी गरीबों को रोजगार प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, जिसमें महिला श्रमिकों की भागीदारी 80% से अधिक है। हालांकि, इसके कार्यान्वयन में कई चुनौतियाँ सामने आई हैं, जिनमें कम मजदूरी दर, जन आधार कार्ड की अनिवार्यता के कारण बहिष्करण, भुगतान में देरी और स्टाफ की कमी शामिल हैं। ये चुनौतियाँ भौगोलिक रूप से असमान प्रभाव डालती हैं, जिससे विभिन्न शहरी क्षेत्रों में श्रमिकों की भागीदारी और योजना की विश्वसनीयता प्रभावित होती है। रिपोर्ट में इन चुनौतियों का समाधान करने के लिए भौगोलिक रूप से लक्षित हस्तक्षेपों, जैसे कार्यस्थलों को गरीब बस्तियों के करीब लाना, मजदूरी में सुधार, जन आधार संबंधी मुद्दों को हल करना और डेटा पारदर्शिता बढ़ाना, की सिफारिश की गई है। अंततः, योजना की सफलता जयपुर के विशिष्ट शहरी संदर्भों के अनुकूलन और प्रभावी निगरानी पर निर्भर करेगी ताकि शहरी गरीबों को अधिकतम लाभ मिल सके।

Manuscript Information

- **ISSN No:** 3139-6313
- **Received:** 13-07-2026
- **Accepted:** 28-08-2026
- **Published:** 31-08-2026
- **IJCRP:**1(4); 2026: 215-220
- **©2026, All Rights Reserved**
- **Plagiarism Checked:** Yes
- **Peer Review Process:** Yes

How to Cite this Article

आरा त, सिंह रा भा. जयपुर जिले में इंदिरा गांधी शहरी रोजगार योजना: एक भौगोलिक विश्लेषण. Int. J. Creative Res. Publ. 2026;1(4):215-220.

Access this Article Online

www.jcrp.in

मूल शब्द: इंदिरा गांधी शहरी रोजगार योजना, मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना, जयपुर जिला, शहरी रोजगार, रोजगार गारंटी, भौगोलिक विश्लेषण, शहरी गरीबी, राजस्थान, जन आधार, कार्यस्थल, चुनौतियाँ, सुधार, महिला भागीदारी, शहरी विकास।

© 2026 तब्बसुम आरा, डॉ. राम भावत सिंह. This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY NC ND).https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

1. प्रस्तावना

इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना (**IGSRY**), जिसे अब मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना के नाम से जाना जाता है, राजस्थान सरकार द्वारा शहरी क्षेत्रों में बढ़ती गरीबी और बेरोजगारी की समस्या को संबोधित करने के लिए शुरू की गई एक महत्वपूर्ण पहल है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (**MGNREGA**) की तर्ज पर तैयार की गई यह योजना, शहरी गरीबों को आजीविका सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से सितंबर **2022** में शुरू की गई थी। इसका प्राथमिक लक्ष्य शहरी परिवारों को प्रति वर्ष **100** दिन का गारंटीशुदा रोजगार उपलब्ध कराना था, जिसे बाद में **125** दिन तक बढ़ा दिया गया।

यह रिपोर्ट विशेष रूप से जयपुर जिले में **IGSRY** के कार्यान्वयन, पहुंच, चुनौतियों और प्रभावों का भौगोलिक परिप्रेक्ष्य से विश्लेषण करती है। जयपुर, जो राज्य की राजधानी है, तीव्र शहरीकरण और रोजगार की चुनौतियों का एक अनूठा मिश्रण प्रस्तुत करता है। यहां की बड़ी आबादी और विविध शहरी परिदृश्य योजना के कार्यान्वयन के लिए विशिष्ट संदर्भ प्रदान करते हैं। इस विश्लेषण का उद्देश्य योजना की ताकत और कमजोरियों को उजागर करना है, साथ ही जयपुर के संदर्भ में सुधार के लिए भौगोलिक रूप से लक्षित सिफारिशें भी प्रदान करना है।

शहरीकरण और रोजगार गारंटी के बीच का संबंध इस योजना के मूल में है। योजना के पीछे का एक मुख्य विचार शहरी क्षेत्रों में बढ़ती गरीबी और बेरोजगारी/अल्प-रोजगार की समस्या को संबोधित करना था। ग्रामीण क्षेत्रों में **MGNREGA** की सफलता को देखते हुए, सरकार ने शहरी संदर्भ में भी इसी तरह के मॉडल को लागू करने का निर्णय लिया, जिससे यह स्पष्ट होता है कि शहरीकरण के साथ आने वाली विशिष्ट रोजगार चुनौतियों को स्वीकार किया गया है। शहरी क्षेत्रों में अनौपचारिक क्षेत्र का प्रभुत्व और मौसमी रोजगार की कमी एक स्थिर आय स्रोत की आवश्यकता को बढ़ाती है। इस प्रकार, **IGSRY** केवल एक रोजगार योजना नहीं है, बल्कि तीव्र शहरीकरण के सामाजिक-आर्थिक परिणामों को कम करने के लिए एक नीतिगत प्रतिक्रिया है। इसका एक महत्वपूर्ण भौगोलिक निहितार्थ यह है कि योजना को शहरी गरीबी के हॉटस्पॉट और अनौपचारिक श्रमिकों की उच्च सांद्रता वाले क्षेत्रों में अधिक प्रभावी ढंग से लक्षित किया जाना चाहिए ताकि इसकी अधिकतम पहुंच और प्रभाव सुनिश्चित हो सके।

2. इंदिरा गांधी शहरी रोजगार योजना: एक व्यापक अवलोकन

इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना का मुख्य उद्देश्य शहरी क्षेत्र में निवास कर रहे प्रत्येक परिवार को एक वित्तीय वर्ष में **100** दिवस का गारंटीशुदा रोजगार उपलब्ध करवाकर उनकी आजीविका की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। बाद में, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बजट **2023-24** में इसे बढ़ाकर **125** दिन करने का प्रस्ताव अनुमोदित किया, जो **1** अप्रैल **2023** से प्रभावी हुआ, जिससे लगभग **₹1100** करोड़ का अतिरिक्त व्यय संभावित है।

योजना के तहत पात्रता मानदंड निर्धारित किए गए हैं। राजस्थान राज्य के किसी भी शहरी स्थानीय निकाय क्षेत्राधिकार में निवास करने वाले **18** वर्ष से **60** वर्ष तक की उम्र के सदस्य इस योजना के लिए पात्र हैं। कुछ स्रोतों में आयु सीमा **18** से **80** वर्ष तक भी बताई गई है। परिवार के पंजीकरण हेतु जन आधार कार्ड अनिवार्य है, और जन आधार कार्ड यूनिट को ही परिवार यूनिट माना जाता है।

योजना के तहत श्रम-आधारित कार्यों को प्राथमिकता दी जाती है। इसमें जल संरक्षण, विरासत संरक्षण, उद्यान/पार्क रखरखाव, साफ-सफाई, ठोस कचरा प्रबंधन, सार्वजनिक स्थानों पर पौधारोपण, बेसहारा पशुओं का प्रबंधन, पार्किंग विकास और अन्य सामुदायिक-उन्मुख कार्य शामिल हैं। सामान्य प्रकृति के कार्यों में निर्माण सामग्री लागत और पारिश्रमिक भुगतान का अनुपात (**Material : Labour Ratio) 25:75** निर्धारित किया गया है, जिसमें पारिश्रमिक भत्ता भुगतान न्यूनतम **75** प्रतिशत होना आवश्यक है। श्रमिकों को श्रम विभाग द्वारा अधिसूचित न्यूनतम मजदूरी दरों पर ऑनलाइन भुगतान किया जाता है, और महिला तथा पुरुष श्रमिकों को समान दर से मजदूरी का भुगतान सुनिश्चित किया जाता है।

इस योजना का शुभारंभ **9** सितंबर **2022** को खानिया की बावड़ी, जयपुर से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा किया गया था। योजना के लिए वित्तीय वर्ष **2022-23** में **₹800** करोड़ का वार्षिक प्रावधान किया गया था।

हाल ही में, पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार की "इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना" का नाम बदलकर "मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना" कर दिया गया है। यह नाम परिवर्तन केवल एक शाब्दिक बदलाव से कहीं अधिक है; यह एक राजनीतिक और नीतिगत बदलाव को दर्शाता है। आमतौर पर, ऐसी योजनाओं का नामकरण वर्तमान सरकार की विचारधारा या प्राथमिकताओं को दर्शाता है। यदि, जैसा कि एक रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है , नई सरकार ने योजना के तहत किसी भी व्यक्ति को रोजगार नहीं दिया है और योजना को पहले ही बंद कर दिया है, तो यह योजना के भविष्य और शहरी रोजगार गारंटी के प्रति राज्य की प्रतिबद्धता पर गंभीर भौगोलिक और सामाजिक-आर्थिक प्रभाव डाल सकता है। भौगोलिक रूप से, इसका अर्थ यह हो सकता है कि जिन शहरी क्षेत्रों ने इस योजना पर भरोसा किया था, उन्हें अब वैकल्पिक रोजगार स्रोतों की तलाश करनी पड़ सकती है, जिससे स्थानीय अर्थव्यवस्थाओं पर दबाव बढ़ सकता है।

योजना में कार्य दिवसों को **100** से बढ़ाकर **125** करने का निर्णय केवल एक संख्यात्मक वृद्धि नहीं है, बल्कि शहरी गरीब परिवारों के लिए बढ़ी हुई आजीविका सुरक्षा का प्रतीक है। **25** अतिरिक्त दिनों का रोजगार प्रति परिवार महत्वपूर्ण अतिरिक्त आय प्रदान करता है, जिससे उनकी क्रय शक्ति बढ़ती है और स्थानीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलता है। यह वृद्धि शहरी क्षेत्रों में गरीबी उन्मूलन के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। भौगोलिक रूप से, इसका अर्थ यह हो सकता है कि योजना के तहत अधिक मानव-दिवस सृजित होंगे, जिससे शहरी स्थानीय निकायों (**ULBs**) पर अधिक कार्यों की पहचान करने और श्रमिकों को नियोजित करने का दबाव पड़ेगा। यह उन क्षेत्रों में अधिक दृश्यमान प्रभाव डाल सकता है जहां योजना का कार्यान्वयन मजबूत है।

तालिका 1: इंदिरा गांधी शहरी रोजगार योजना - मुख्य विशेषताएं

विशेषता	विवरण
योजना का नाम (पुराना)	इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना

© 2026 तब्बसुम आरा, डॉ. राम भावत सिंह. This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY NC ND).https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

योजना का नाम (नया)	मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना
शुभारंभ तिथि	**9** सितंबर **2022**
शुभारंभ स्थल	खानिया की बावड़ी, जयपुर
मुख्य उद्देश्य	शहरी परिवारों को आजीविका सुरक्षा हेतु गारंटीशुदा रोजगार
पात्रता मानदंड	**18-60** वर्ष के शहरी निवासी, जन आधार कार्ड अनिवार्य
कार्य दिवस (प्रारंभिक)	प्रति परिवार **100** दिन
कार्य दिवस (संशोधित)	प्रति परिवार **125** दिन (**1** अप्रैल **2023** से प्रभावी)
वार्षिक बजट प्रावधान (प्रारंभिक)	**₹800** करोड़
प्रमुख कार्य प्रकार	जल संरक्षण, विरासत संरक्षण, उद्यान/पार्क रखरखाव, साफ-सफाई, ठोस कचरा प्रबंधन, पौधारोपण
सामग्री:श्रम अनुपात	**25:75** (सामान्य कार्यों में)

3. जयपुर जिले में योजना का क्रियान्वयन और प्रशासनिक ढाँचा

जयपुर जिले में योजना के क्रियान्वयन हेतु प्रारंभिक निर्देश जिला कलेक्टर राजन विशाल द्वारा दिए गए थे। उन्होंने शहरी क्षेत्रों में रोजगार चाहने वाले परिवारों की पहचान करने और पात्र श्रमिकों के आकलन के निर्देश दिए थे। योजना के शुभारंभ से पहले ही कार्यों के लिए प्रशासनिक और वित्तीय स्वीकृतियां जारी करने और उन्हें पोर्टल पर अपलोड करने पर जोर दिया गया था। बेहतर संचालन और कार्यान्वयन के लिए शहरी निकायों में **IGSRY** प्रकोष्ठ (सेल्स) के गठन का निर्देश दिया गया था। इसके अतिरिक्त, नगरपालिकाओं, नगर परिषदों और नगर निगमों में संविदा पदों पर कर्मचारियों की नियुक्ति को राज्य सरकार द्वारा स्वीकृति दी गई थी, ताकि योजना का सुचारु संचालन सुनिश्चित किया जा सके।

जयपुर में योजना का संचालन जयपुर नगर निगम (हेरिटेज और ग्रेटर) के तहत किया जाता है। जयपुर नगर निगम हेरिटेज ने शहर को चमकाने और सुंदर बनाने के लिए योजना के तहत **₹13.08** करोड़ की लागत के **172** कार्यों के प्रस्ताव तैयार किए थे। इन प्रस्तावों में **₹1.56** करोड़ सामग्री पर और **₹11.51** करोड़ श्रम पर खर्च करने की योजना थी, जिससे **4.38** लाख लोगों को रोजगार मिल सके। योजना के संचालन हेतु स्थानीय निकाय विभाग तथा निकाय स्तर पर योजना प्रकोष्ठ गठित किए गए हैं।

जयपुर नगर निगम हेरिटेज के तहत विभिन्न जोन में कार्यों का वितरण किया गया है, जो योजना के विकेन्द्रीकृत कार्यान्वयन को दर्शाता है। आदर्श नगर जोन में **₹2.52** करोड़ की लागत के **38** कार्य, अधिशाषी मुख्यालय स्तर पर **₹1.58** करोड़ के **6** कार्य, सिविल लाइन जोन में **₹68** लाख के **26** कार्य, हवामहल-आमेर जोन में प्रथम क्षेत्र में **₹2.20** करोड़ के **38** कार्य और द्वितीय क्षेत्र में **₹1.50** करोड़ के **17** कार्य प्रस्तावित थे। इसके अतिरिक्त, किशनपोल जोन में **₹39.85** लाख की लागत के **45** कार्य, उद्यान शाखा में **₹2.15** करोड़ के **32** कार्य और पशु प्रबंधन शाखा में **₹2.03** करोड़ के **7** कार्य किए जाने की योजना थी।

तालिका 2: जयपुर नगर निगम हेरिटेज में प्रस्तावित कार्य और अनुमानित लागत

जोन का नाम	प्रस्तावित कार्यों की संख्या	अनुमानित लागत (₹ करोड़ में)	सामग्री पर खर्च (₹ करोड़ में)	श्रम पर खर्च (₹ करोड़ में)	संभावित रोजगार (लाख लोगों में)
आदर्श नगर जोन	**38**	**2.52**	-	-	-
अधिशाषी मुख्यालय स्तर	**6**	**1.58**	-	-	-
सिविल लाइन जोन	**26**	**0.68**	-	-	-
हवामहल-आमेर जोन (प्रथम)	**38**	**2.20**	-	-	-
हवामहल-आमेर जोन (द्वितीय)	**17**	**1.50**	-	-	-
किशनपोल जोन	**45**	**0.39**	-	-	-
उद्यान शाखा	**32**	**2.15**	-	-	-
पशु प्रबंधन शाखा	**7**	**2.03**	-	-	-
कुल	**172**	**13.08**	**1.56**	**11.51**	**4.38**

जयपुर में योजना का कार्यान्वयन विकेन्द्रीकृत तरीके से किया जा रहा है, जिसमें स्थानीय आवश्यकताओं और प्राथमिकताओं के अनुसार कार्य आवंटित किए जा रहे हैं। जयपुर में, पर्यावरण संरक्षण, विरासत संरक्षण और स्वच्छता जैसे विशिष्ट कार्य प्रकारों पर जोर दिया गया है। यह दृष्टिकोण स्थानीय जरूरतों के प्रति अधिक प्रतिक्रियाशील हो सकता है, लेकिन यह विभिन्न जोन में कार्यान्वयन की गुणवत्ता और दायरे में असमानता भी पैदा कर सकता है। जयपुर के मामले में, हेरिटेज क्षेत्र होने के कारण विरासत संरक्षण पर जोर समझ में आता है, लेकिन यह सवाल उठता है कि क्या अन्य प्रकार के शहरी विकास कार्यों (जैसे बुनियादी ढांचा) को पर्याप्त रूप से संबोधित किया जा रहा है और क्या ये कार्य सभी श्रमिकों के लिए उपयुक्त हैं।

जयपुर नगर निगम हेरिटेज में प्रस्तावित प्रमुख कार्यों में पर्यावरण संरक्षण के तहत सार्वजनिक स्थानों पर पौधारोपण, उद्यान संधारण, फुटपाथ और डिवाइडर का रखरखाव शामिल है। इसके अतिरिक्त, नगर निकाय, वन, उद्यानिकी और कृषि विभाग के अधीन नर्सरी में पौधे तैयार करना, श्मशान और कब्रिस्तान में सफाई करना, वृक्षारोपण संबंधी कार्य, उद्यानिकी से संबंधित कार्य और वानिकी से संबंधित कार्य भी किए जाते हैं। जल स्रोतों के पुनरुद्धार के तहत तालाब, गिनाणी, बावड़ी, जोहड़ आदि की मिट्टी निकालने का कार्य, सफाई-सुधार संबंधी कार्य, रेन वाटर हार्वेस्टिंग संरचनाओं का निर्माण, मरम्मत और सफाई संबंधी कार्य भी योजना का हिस्सा हैं। स्वच्छता एवं सैनिटेशन के तहत ठोस कचरा प्रबंधन, नगरीय अपशिष्ट

© 2026 तब्बसुम आरा, डॉ. राम भावत सिंह. This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY NC ND).https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

के घर-घर संग्रहण एवं पृथक्करण हेतु श्रमिक कार्य भी किए जाते हैं। ये कार्य स्पष्ट रूप से श्रम-आधारित हैं और इनमें सामग्री की तुलना में श्रम घटक अधिक है, जैसा कि योजना के **25:75** सामग्री-श्रम अनुपात में परिलक्षित होता है। ये कार्य न केवल रोजगार प्रदान करते हैं, बल्कि शहरी पर्यावरण और सार्वजनिक बुनियादी ढांचे में भी सुधार करते हैं। यह योजना शहरी गरीबों को आय प्रदान करने के साथ-साथ शहर के सौंदर्य और पर्यावरणीय स्थिरता में भी योगदान दे रही है। भौगोलिक रूप से, इन कार्यों का प्रभाव उन क्षेत्रों में सबसे अधिक दिखाई देगा जहां वे किए जा रहे हैं, जिससे स्थानीय निवासियों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार होगा। यह एक ऐसी स्थिति को दर्शाता है जहां रोजगार सृजन के साथ-साथ शहरी विकास भी होता है।

4. भौगोलिक विश्लेषण: पहुंच, भागीदारी और कार्य के प्रकार

इंदिरा गांधी शहरी रोजगार योजना राजस्थान के सभी **213** शहरी स्थानीय निकायों (**ULBs**) में लागू की गई है, जिसमें **10** नगर निगम (जयपुर सहित), **34** नगर परिषद और **169** नगर पालिकाएं शामिल हैं। जयपुर में दो नगर निगम हैं: जयपुर ग्रेटर और जयपुर हेरिटेज। जयपुर नगर निगम हेरिटेज के तहत **7** भौगोलिक जोन और **150** वार्ड हैं, जहां योजना के तहत कार्य प्रस्तावित किए गए हैं। हालांकि जयपुर जिले के लिए विशिष्ट, विस्तृत भौगोलिक डेटा (जैसे वार्ड-वार जॉब कार्ड, मांग या कार्य पूर्णता) सीधे सार्वजनिक रूप से उपलब्ध नहीं है, राज्य-स्तरीय **MIS** पोर्टल में जिला, **ULB**, जोन और वार्ड स्तर पर डेटा फ़िल्टर करने की क्षमता है, जो यह दर्शाता है कि ऐसा डेटा एकत्र किया जा रहा है।

योजना के तहत जॉब कार्ड जारी करने, कार्य की मांग और वास्तविक रोजगार के पैटर्न में कुछ महत्वपूर्ण अवलोकन सामने आए हैं। राज्य-स्तर पर, **2022-23** में **2,12,142** जॉब कार्ड जारी किए गए थे, और **43,312** परिवारों में से **63,500** व्यक्तियों ने काम की मांग की थी। सितंबर **2022** में, राज्य में **3** लाख शहरी बेरोजगारों का पंजीकरण हुआ था, जिसमें से **90** हजार लोगों ने काम करने की इच्छा जताई थी। वित्तीय वर्ष **2023-24** में, **3.19** लाख परिवारों को रोजगार आवंटित किया गया, कुल **10,824** कार्य स्वीकृत किए गए, और **202.61** लाख मानव-दिवस सृजित हुए। जयपुर में, नगर निगम जयपुर ग्रेटर और हेरिटेज आयुक्तों ने जोन उपायुक्तों को एक वार्ड से कम से कम **50** लोगों को जोड़ने का लक्ष्य दिया था, लेकिन यह लक्ष्य पूरी तरह से प्राप्त नहीं हो सका। **CRISP** मूल्यांकन के अनुसार, जॉब कार्ड बनाए गए, काम की मांग और वास्तविक उपस्थिति के बीच विसंगतियां देखी गईं, जिसमें काम की मांग करने वाले केवल **32%** श्रमिक ही वास्तव में उपस्थित हुए।

यह विसंगति भौगोलिक रूप से महत्वपूर्ण है। इसका अर्थ यह हो सकता है कि कुछ क्षेत्रों में श्रमिकों को काम की जानकारी नहीं मिल रही है, या काम के स्थान दूर हैं, या मजदूरी इतनी कम है कि वे अन्य विकल्प पसंद करते हैं। जयपुर जैसे बड़े शहर में, परिवहन लागत और काम के स्थानों की दूरी एक बाधा हो सकती है, जिससे श्रमिक विशेष वार्डों या जोन में काम करने से हतोत्साहित हो सकते हैं। यह योजना की पहुंच और प्रभावशीलता को भौगोलिक रूप से सीमित करता है।

जयपुर में किए जा रहे कार्यों के प्रकारों का भौगोलिक वितरण शहर की विशिष्ट आवश्यकताओं को दर्शाता है। **CRISP** रिपोर्ट के अनुसार, राज्य-स्तर पर स्वच्छता कार्य कुल स्वीकृत कार्यों का **57%** थे, इसके बाद पर्यावरण संबंधी कार्य (**17%**) थे। जयपुर नगर निगम हेरिटेज में, पर्यावरण संरक्षण, उद्यान संधारण, जल स्रोतों का पुनरुद्धार, और ठोस कचरा प्रबंधन जैसे कार्यों पर विशेष ध्यान दिया गया है, जो शहर की विशिष्ट आवश्यकताओं और विरासत प्रकृति को दर्शाते हैं। जबकि जयपुर हेरिटेज में विशिष्ट कार्य प्रकारों पर ध्यान केंद्रित करना शहर की पहचान के लिए फायदेमंद है, यह सवाल उठाता है कि क्या यह सभी शहरी गरीब श्रमिकों की कौशल-सेट और रोजगार की जरूरतों को पूरा करता है। भौगोलिक रूप से, यदि कुछ क्षेत्रों में केवल विशिष्ट प्रकार के कार्य उपलब्ध हैं, तो यह उन श्रमिकों के लिए बाधा बन सकता है जिनके पास उन कार्यों के लिए कौशल नहीं है या वे उनमें रुचि नहीं रखते हैं, जिससे योजना की पहुंच सीमित हो सकती है। विविधता की कमी से कुछ भौगोलिक क्षेत्रों में श्रमिकों की भागीदारी कम हो सकती है।

लाभार्थियों की जनसांख्यिकी में महिला भागीदारी एक महत्वपूर्ण पहलू है। राज्य-स्तर पर, योजना के तहत नियोजित **80%** से अधिक श्रमिक महिलाएं हैं। **CRISP** मूल्यांकन में भी **95%** उत्तरदाता महिलाएं थीं, संभवतः **IGSRY** मजदूरी बाजार मजदूरी से कम होने के कारण पुरुषों को आकर्षित करने में विफल रही। जयपुर में भी महिला श्रमिकों की उच्च भागीदारी की संभावना है, जो शहरी गरीब महिलाओं के सशक्तिकरण और आजीविका सुरक्षा में योजना की भूमिका को रेखांकित करता है।

5. क्रियान्वयन में चुनौतियाँ और भौगोलिक निहितार्थ

योजना के क्रियान्वयन में कई चुनौतियाँ सामने आई हैं, जिनके महत्वपूर्ण भौगोलिक निहितार्थ हैं। **CRISP** रिपोर्ट में लंबित भुगतान को श्रमिक भागीदारी को प्रभावित करने वाला एक प्रमुख मुद्दा बताया गया है। गलत बैंक विवरण और तीव्र स्टाफ की कमी भुगतान में देरी के मुख्य कारण थे। इसके अतिरिक्त, **60% IRGY** स्टाफ को प्रशिक्षण नहीं मिला था, और **80%** को अतिरिक्त प्रशिक्षण की आवश्यकता महसूस हुई। स्टाफ की कमी से भुगतान में देरी और कार्यभार में वृद्धि हुई। कई कार्यस्थलों पर पीने के पानी और प्राथमिक उपचार जैसी बुनियादी सुविधाओं का भी अभाव था। ये चुनौतियाँ जयपुर के विभिन्न **ULBs**, जोन और वार्डों में योजना के कार्यान्वयन को असमान रूप से प्रभावित कर सकती हैं। दूरदराज के या कम विकसित शहरी क्षेत्रों में, जहां निगरानी और स्टाफ की उपलब्धता कम हो सकती है, इन समस्याओं का प्रभाव अधिक गंभीर हो सकता है, जिससे श्रमिकों की भागीदारी और योजना की विश्वसनीयता कम हो सकती है।

प्रशासनिक अक्षमता के ये संकेत केवल राज्य-स्तर पर ही नहीं, बल्कि जयपुर के भीतर विभिन्न **ULBs** और जोन में भी कार्यान्वयन की गुणवत्ता को प्रभावित करते हैं। कुछ क्षेत्रों में बेहतर प्रशासनिक क्षमता हो सकती है, जबकि अन्य में इन चुनौतियों का सामना अधिक करना पड़ सकता है, जिससे भौगोलिक असमानता पैदा होगी। प्रशासनिक अक्षमता सीधे तौर पर योजना की प्रभावशीलता को कम करती है। भौगोलिक रूप से, इसका अर्थ है कि जयपुर के कुछ हिस्सों में श्रमिक समय पर भुगतान प्राप्त कर सकते हैं और बेहतर कार्यस्थल सुविधाओं का अनुभव कर सकते हैं, जबकि अन्य क्षेत्रों में उन्हें निराशा और बहिष्करण का सामना करना पड़ सकता है। यह योजना के प्रति विश्वास को कम कर सकता है और उन क्षेत्रों में भागीदारी को हतोत्साहित कर सकता है जहां प्रशासनिक सहायता कमजोर है।

© 2026 तब्बसुम आरा, डॉ. राम भावत सिंह. This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY NC ND).https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

जन आधार कार्ड की अनिवार्यता से उत्पन्न बहिष्करण एक और महत्वपूर्ण भौगोलिक पहलू है। जन आधार कार्ड योजना के तहत पंजीकरण के लिए अनिवार्य है। हालांकि, जन आधार की पैठ अभी भी कम है; **2023** तक, राजस्थान में कुल परिवारों का केवल **15%** ही जन आधार के तहत पंजीकृत था। जन आधार की कम पैठ भौगोलिक रूप से असमान हो सकती है। शहरी क्षेत्रों में, विशेष रूप से प्रवासी श्रमिकों या हाल ही में शहरी क्षेत्रों में आए लोगों के लिए जन आधार कार्ड प्राप्त करना मुश्किल हो सकता है। यह जयपुर के उन क्षेत्रों में अधिक स्पष्ट हो सकता है जहां अनौपचारिक बस्तियां या प्रवासी आबादी अधिक है, जिससे इन कमजोर समूहों को योजना के लाभों से बाहर रखा जा सकता है। यह योजना शहरी प्रवासियों को लक्षित करने में विफल हो सकती है, जो अक्सर सबसे कमजोर और रोजगार के सबसे अधिक जरूरतमंद होते हैं। भौगोलिक रूप से, इसका अर्थ है कि जयपुर के उन क्षेत्रों में जहां प्रवासी श्रमिकों की उच्च सांद्रता है (जैसे औद्योगिक क्षेत्र या निर्माण स्थल के पास की बस्तियां), योजना की पहुंच गंभीर रूप से सीमित हो सकती है, जिससे इन समुदायों में बेरोजगारी और गरीबी बनी रहेगी। **CRISP** रिपोर्ट में प्रवासियों के लिए पंजीकृत पते के बाहर **ULBs** में कार्य आवंटन की अनुमति देने की सिफारिश इस समस्या को स्वीकार करती है।

कम मजदूरी दरों का श्रमिक भागीदारी पर भी भौगोलिक प्रभाव पड़ता है। अकुशल श्रमिक को **₹259** प्रति कार्य दिवस, मेट को **₹271** और कुशल श्रमिक को **₹283** प्रतिदिन मजदूरी दी जाती है। यह मजदूरी दिहाड़ी मजदूर को मिलने वाली बाजार मजदूरी से दोगुनी कम है, जिसके कारण योजना में लोगों की रुचि कम है और मजदूर नहीं मिल रहे हैं। कम मजदूरी दर का प्रभाव भौगोलिक रूप से भिन्न हो सकता है। जयपुर जैसे बड़े शहरों में, जहां बाजार मजदूरी अधिक हो सकती है और रोजगार के अधिक विकल्प उपलब्ध हो सकते हैं, श्रमिकों के लिए **IGSRY** में काम करने की प्रेरणा कम हो सकती है। इसके विपरीत, छोटे शहरी निकायों या कम आर्थिक अवसरों वाले क्षेत्रों में, जहां बाजार मजदूरी भी कम हो सकती है, **IGSRY** की मजदूरी अधिक आकर्षक लग सकती है, जिससे वहां भागीदारी अधिक हो सकती है। यह जयपुर के भीतर भी विभिन्न आर्थिक क्षेत्रों में योजना की सफलता को प्रभावित कर सकता है।

6. सुधार हेतु सुझाव और भविष्य की दिशा

जयपुर जिले में योजना के बेहतर क्रियान्वयन हेतु भौगोलिक रूप से लक्षित सिफारिशें आवश्यक हैं। श्रमिकों के लिए परिवहन लागत और पहुंच की बाधाओं को कम करने के लिए, कार्यस्थलों की पहचान और आवंटन गरीब बस्तियों और श्रमिक निवासों की भौगोलिक निकटता के आधार पर किया जाना चाहिए। **CRISP** रिपोर्ट में सुझाए गए अनुसार, कार्यों के दायरे का विस्तार किया जाना चाहिए, जिसमें विरासत संरक्षण/प्रबंधन, अंतर-विभागीय अभिसरण, और सेवा प्रावधान शामिल हों। जयपुर में, यह ऐतिहासिक स्थलों, बाजारों और सार्वजनिक उपयोगिताओं के रखरखाव जैसे कार्यों को शामिल कर सकता है। जॉब कार्ड पंजीकरण और काम की मांग के लिए जिला-स्तरीय समितियों की स्थापना की जाए। अपशिष्ट प्रबंधन में उनकी भागीदारी के लिए कचरा बीनने वाले समुदायों तक पहुंच बनाई जाए। श्रमिकों के पंजीकरण और काम की मांग को सुविधाजनक बनाने के लिए श्रम चौकों पर विशेष शिविर लगाए जाएं।

इन सिफारिशों का भौगोलिक अनुप्रयोग महत्वपूर्ण है। उदाहरण के लिए, कार्यस्थलों को गरीब बस्तियों के करीब लाना जयपुर के उन क्षेत्रों पर विशेष रूप से लागू होता है जहां श्रमिक दूरदराज के क्षेत्रों से आते हैं या जहां परिवहन महंगा है। नए कार्यों को जोड़ना जयपुर के विभिन्न जोन में विशिष्ट शहरी विकास आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए महत्वपूर्ण है। सिफारिशों को जयपुर के विशिष्ट भौगोलिक और सामाजिक-आर्थिक संदर्भ में अनुकूलित किया जाना चाहिए। उदाहरण के लिए, जयपुर के हेरिटेज जोन में विरासत संरक्षण पर अधिक ध्यान केंद्रित किया जा सकता है, जबकि बाहरी, तेजी से शहरीकरण वाले क्षेत्रों में बुनियादी ढांचा विकास और स्वच्छता पर जोर दिया जा सकता है। यह योजना की प्रभावशीलता और स्थानीय प्रासंगिकता को बढ़ाएगा।

श्रमिक भागीदारी बढ़ाने, भुगतान में तेजी लाने और स्टाफ क्षमता निर्माण के लिए भी कई सुझाव दिए गए हैं। **IGSRY** मजदूरी को अन्य राज्यों की तुलना में प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए संशोधित किया जाना चाहिए, ताकि अधिक श्रमिकों, विशेषकर पुरुषों को आकर्षित किया जा सके। भुगतान में देरी को कम करने के लिए साप्ताहिक मजदूरी भुगतान लागू किया जाए। भुगतान में देरी और कार्यभार को कम करने के लिए स्टाफ रिक्तियों को भरा जाए। भुगतान अस्वीकृति से बचने के लिए सक्रिय रूप से बैंक विवरण अपडेट किए जाएं। **IRGY** कार्यकर्मियों को उनकी नौकरी की भूमिकाओं के अनुसार प्रशिक्षित किया जाए।

डेटा पारदर्शिता और निगरानी में सुधार के लिए प्रबंधन सूचना प्रणाली (**MIS**) को सार्वजनिक किया जाना चाहिए। हालांकि, वर्तमान में, **MIS** पोर्टल पर जयपुर-विशिष्ट विस्तृत डेटा सीधे उपलब्ध नहीं है, जो एक महत्वपूर्ण डेटा अंतर को दर्शाता है। इस डेटा अंतराल का मतलब है कि योजना के भौगोलिक प्रभाव का सटीक मूल्यांकन करना मुश्किल है। भविष्य में, जयपुर के भीतर वार्ड-वार या जोन-वार जॉब कार्ड जारी करने, काम की मांग, वास्तविक उपस्थिति, कार्य पूर्णता और भुगतान की स्थिति पर अधिक विस्तृत और सार्वजनिक रूप से सुलभ डेटा की आवश्यकता है। यह नीति निर्माताओं को योजना के कार्यान्वयन में भौगोलिक असमानताओं की पहचान करने और लक्षित हस्तक्षेप करने में सक्षम बनाएगा।

योजना को कौशल विकास से जोड़ने और टूल किट प्रदान करने के सुझाव भी दिए गए हैं। इंटर्नशिप के माध्यम से कौशल विकास को योजना के साथ एकीकृत किया जाना चाहिए। स्वच्छता श्रमिकों के लिए टूल किट प्रदान किए जाने चाहिए। **ULBs** को वस्तुनिष्ठ मापदंडों के आधार पर रैंक किया जाना चाहिए ताकि प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा मिल सके। **ULB** स्तर पर हेल्प डेस्क और हेल्पलाइन को मजबूत किया जाना चाहिए। कार्यस्थल सुविधाओं को अनिवार्य किया जाना चाहिए और चोटों के लिए मुआवजा प्रदान किया जाना चाहिए। कर्मचारियों के लिए अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (**FAQ**) दस्तावेजों और वीडियो ट्यूटोरियल का एक भंडार संकलित किया जाना चाहिए।

© 2026 तब्बसुम आरा, डॉ. राम भावत सिंह. This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY NC ND).https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

तालिका 3: योजना के तहत राज्य-स्तरीय प्रगति (2023-24)

वित्तीय वर्ष	रोजगार आवंटित परिवारों की संख्या	स्वीकृत कार्यों की कुल संख्या	सृजित मानव-दिवस	महिला श्रमिकों की भागीदारी (%)	भुगतान की गई राशि (₹ करोड़ में)
2023-24	3.19 लाख	10,824	202.61 लाख	80% से अधिक	339

यह तालिका योजना की समग्र प्रगति और पैमाने का एक स्नैपशॉट प्रदान करती है। चूंकि जयपुर-विशिष्ट समेकित प्रगति रिपोर्ट डेटा सीधे उपलब्ध नहीं है, राज्य-स्तरीय डेटा का उपयोग व्यापक रुझानों को समझने के लिए किया जा सकता है जो जयपुर पर भी लागू होते हैं। यह तालिका योजना की सफलता के प्रमुख संकेतकों को सारांशित करती है, जैसे कि सृजित मानव-दिवस और महिला भागीदारी, जो योजना के सामाजिक प्रभाव को उजागर करती है। यह इस बात पर भी बल देती है कि अधिक भौगोलिक रूप से विस्तृत डेटा की आवश्यकता है।

7. निष्कर्ष

जयपुर जिले में इंदिरा गांधी शहरी रोजगार योजना (अब मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना) ने शहरी गरीबों को रोजगार प्रदान करने और शहरी बुनियादी ढांचे में सुधार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, जैसा कि राज्य-स्तर पर सृजित मानव-दिवस और महिला भागीदारी से स्पष्ट है। जयपुर में, योजना ने शहर के सौंदर्य और पर्यावरण संरक्षण में योगदान दिया है, विशेष रूप से जयपुर हेरिटेज नगर निगम के तहत प्रस्तावित कार्यों के माध्यम से। यह योजना शहरी गरीबों के लिए एक महत्वपूर्ण सामाजिक सुरक्षा जाल के रूप में कार्य करती है, जो उन्हें आर्थिक अनिश्चितताओं से बचाती है।

हालांकि, मजदूरी दरों, जन आधार की पैठ, भुगतान में देरी और स्टाफ की कमी जैसी चुनौतियां योजना की पूर्ण क्षमता को बाधित कर रही हैं, खासकर जयपुर जैसे बड़े और विविध शहर में। जॉब कार्ड जारी करने, काम की मांग और वास्तविक उपस्थिति के बीच की विसंगतियां, साथ ही जन आधार की अनिवार्यता के कारण बहिष्करण, योजना की पहुंच और प्रभावशीलता को भौगोलिक रूप से सीमित करते हैं। प्रशासनिक अक्षमताएं विभिन्न क्षेत्रों में कार्यान्वयन की गुणवत्ता में असमानता पैदा कर सकती हैं, जिससे योजना के प्रति विश्वास कम हो सकता है।

भविष्य में, योजना की सफलता जयपुर के विशिष्ट भौगोलिक संदर्भों के लिए लक्षित हस्तक्षेपों पर निर्भर करेगी। इसमें कार्य प्रकारों का विविधीकरण शामिल है, ताकि वे सभी श्रमिकों की कौशल-सेट और शहरी विकास की विविध आवश्यकताओं को पूरा कर सकें। मजदूरी में सुधार, जन आधार बहिष्करण को संबोधित करना, और स्थानीय स्तर पर प्रशासनिक क्षमताओं को मजबूत करना भी महत्वपूर्ण है। अंततः, अधिक विस्तृत और सार्वजनिक भौगोलिक डेटा की उपलब्धता योजना की प्रभावशीलता का बेहतर मूल्यांकन करने और भविष्य की नीतियों को सूचित करने के लिए महत्वपूर्ण होगी, जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि योजना जयपुर के शहरी गरीबों को अधिकतम लाभ प्रदान करे।

संदर्भ सूची

1. Aaj Tak. Ashok Gehlot Rajasthan Assembly Elections Indira Gandhi Urban Employment Guarantee Scheme. 2022 Sep 9.
2. Centre for Research in Schemes and Policies (CRISP). IGRY concurrent evaluation report. 2023.
3. Comptroller and Auditor General of India. Report No. 10 of the year 2022. New Delhi: CAG of India; 2022.
4. CrackitToday Affairs. Indira Gandhi Shehari Rojgar Yojana.
5. Dainik Navajyoti. Low interest of people in Indira Gandhi Urban Employment Guarantee Scheme.
6. Economic Times. Urban Employment Scheme: Rajasthan govt approves guidelines for implementation of new urban employment scheme. 2022 May 22.
7. Government of Rajasthan, Department of Local Self Government. Approved guidelines for Indira Gandhi Shehri Rojgar Yojana.
8. Government of Rajasthan, Directorate of Economics and Statistics. Economic review 2023-24. Jaipur: Government of Rajasthan; 2024.
9. Government of Rajasthan, Local Self Government Department. Office Lens 08092022.
10. Govtschemes. in. Indira Gandhi Shehri Rojgar Yojana.
11. Jaipur Municipal Corporation. City profile.
12. Jaipur: Jaipur Municipal Corporation.
13. Jansoochna Portal, Government of Rajasthan. List of schemes.
14. Mukhyamantri Shehri Rojgar Guarantee Yojana, Government of Rajasthan. Official portal.
15. Mukhyamantri Shehri Rojgar Guarantee Yojana, Government of Rajasthan. Muster list search.
16. Mukhyamantri Shehri Rojgar Guarantee Yojana, Government of Rajasthan. Work summary report.
17. Mukhyamantri Shehri Rojgar Guarantee Yojana, Government of Rajasthan. Family demand summary.
18. Navbharat Times. Gehlot approves new guidelines for implementation of Indira Gandhi Shahari Rozgar Yojana. 2022 May 22.
19. Patrika. BJP government has committed a great sin by changing the name of Indira Gandhi Urban Guarantee Employment Scheme: Khachariyawas.

© 2026 तब्बसुम आरा, डॉ. राम भावत सिंह. This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY NC ND).https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

20. Rajras.in. Indira Gandhi Shahri Rojgar Yojna.
21. ResearchGate. Mandatory Jan Adhaar for availing job card under Rajasthan's Urban Employment Guarantee Scheme IGSRY: Matter of exclusion.
22. Testbook. Under Indira Gandhi Shahri Rojgar Guarantee Scheme.Times Now Hindi. Jaipur Corporation Heritage's proposal prepared under Indira Gandhi Urban Employment Scheme.
23. Times of India. Identify families seeking jobs in urban areas: DC. 2022 May 28.

Creative Commons (CC) License

This article is an open-access article distributed under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution–Non-Commercial–No Derivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0) license. This license permits sharing and redistribution of the article in any medium or format for non-commercial purposes only, provided that appropriate credit is given to the original author(s) and source. No modifications, adaptations, or derivative works are permitted under this license.

तब्बसुम आरा शोधार्थी हैं और ज्योति विद्यापीठ महिला विश्वविद्यालय, जयपुर, राजस्थान, भारत में शोध कार्य कर रही हैं। उनका अकादमिक कार्य शोध, अध्ययन एवं विषयगत ज्ञान के विकास पर केंद्रित है। वे उच्च शिक्षा के क्षेत्र में सक्रिय रहते हुए अनुसंधानात्मक दृष्टिकोण और शैक्षणिक रुचियों को निरंतर विकसित कर रही हैं।

© 2026 तब्बसुम आरा, डॉ. राम भावत सिंह. This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY NC ND).https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/